को लागू करने की बात कही है और लागू कर दिया है, लेकिन भारत इसमें पीछे हैं।

महोदय, यह फैसला तो होना चाहिए। या तो युनिफोर्म सिविल कोड पास करिए या फिर जिन लोगों की भावनाओं को देखकर, जो आपके पास रेकमेंडेशन्स आई हुई है , उन पर विचार करते हुए आनदं मैरिज एक्ट भारत में भी तुरंत लागू हो और उस पर आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री हंसराज भारद्वाज : जनाब, मैं अहलुवालिया जी की तरह दो लैंग्वेज में नहीं बोलता। यहां पाकिस्तान की बात नहीं है, हमारे अपने दिल में बहुत .....(**व्यवधान**)....

श्री एस0 एस0 अहलुवालिया : पाकिस्तान की बात इसलिए है क्योंकि लोग वहां जाकर कर आएंगे।

श्री हसंराज भारद्वाज : यहां पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बात थोडे ना हो रही है, हमारी अपनी पार्लियामेंट की बात हो रही है। आज तरलोचन सिंह जी ने यह बात कही है और माननीय सदस्यों ने not only Sikh, but also there is a wide demand that the marriage under the Anand Karaj Act is the best form of marriage. इसको जल्दी करना है, तो मैंने पार्लियामेंट में खडे हो कर कह दिया है कि हम इसको जल्द से जल्द कराएंगे।

श्री एस0 एस0 अहलुवालिया : आप इसको बजट सैशन में ले आइए। ....(**व्यवधान**).... बजट सैशन में ले आइए और पास कराइए।

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, in 1967, the DMK Government amended the Hindu Marriage Act and recognised marriages which are devoid of any religious ceremony as valid. The Chief Minister has also written to the Union Government for amending the Act on a national level. Will the Government consider this matter?

SHRI H.R. BHARDWAJ: Sir, this issue comes under the Concurrent List. Mostly, the State Legislatures do take their own decisions within the States. There are several States which have already enacted laws and registration is provided there. But, since this matter was taken up by the Supreme Court, it was desired that there should be some sort of certainty about registration of women marriages to protect the interest of women. So, a concerted effort is being made to harmonise this law so that there is no difficulty in any faith or any religion, when the women suffer. They need protection of law and there should be presumption about the marriage and they should produce the certificate. This is a very laudable object. There is no need of any controversy.

शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जाना

*142. **श्री मंगनी लाल मंडल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक मानकों की तुलना में योग्यता, मेधा, शोध और व्यवसायात्मक नहीं है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का द्रष्टिकोण क्या है,

(ग) क्या यह सच है कि देश में शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने तथा उच्च शिक्षा को विश्वस्तरीय ज्ञान और शोध आधारित बनाने के लिए एक क्रांतिकारी योजना लागू की जानी है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी0 पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) से (घ) जी, नहीं । भारत में शिक्षा प्रणाली जहां योग्यता एवं उत्कृष्ट्ता का संवध करने का प्रयास करती है वहीं अपनी सामाजिक तथा आर्थिक प्राथमिकताओं को पूरा करते हुए शिक्षा को समान रूप से सुलभ बनाने को भी बढावा देती है तथा इसे समाज के लिए अनुकूल भी बनाती है । शैक्षिक सुधार एक सतत प्रक्रिया है तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में संस्थागत तथा नीतिगत सुधारों के माध्यम से तथा सार्वजनिक व्यय को बढाकर शिक्षा के विस्तार, समावेश तथा कोटि में त्वरित सुधार के माध्यम से सुधारों को आगे बढाने का प्रावधान है । यह वास्तविकता है कि हमारी उच्चतर शिक्षा प्रणाली में शोध प्रयासों में काफी सुधार की गुंजाइश है । भारतीय विश्वविद्यालयों में पीएच0डी0 अध्येताओं की संख्या बढाना, विश्वविद्यालयों तथा वैज्ञानिक शोध संस्थाओं में ताल मेल सुदृढ करना, स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में शोध घटक का महत्तर समावेशन, विश्वविद्यालयों में सहयोगात्मक अनुसंधान की संवर्धन, शोध संबंधी बुनियादी सुविधाओं का सुदृढकरण, शोध पदों का सृजन तथा अध्येतावृत्तियों में वृद्वि करना ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित अनिवार्य सुधार हैं ।

Reforming the Educational System

t*142. SHRI MANGANI LAL MANDAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the educational system of the country is not merit, excellence, research and profession-oriented, as compared to global standards;

(b) if so, the details thereof and Government's approach in this regard;

(c) whether it is a fact that a radical scheme is proposed to be implemented, to bring about basic changes in the education system of the country and to make higher education knowledge and research-oriented of international standards; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) No, Sir. The education system in India tries to promote merit and excellence, while also promoting equity in access and makes it relevant to the society by catering to its social and economic priorities. Educational Reform is a continuing process and the Eleventh Five Year Plan seeks to carry them forward through expansion, inclusion and rapid improvement in quality, through institutional and policy reforms and by enhancing public spending. It is true that research efforts in our higher education system has a considerable scope for improvement. Increasing the number of Ph.Ds from Indian universities strengthening linkages between the universities and the Scientific Research Institutions, inclusion of greater research component in Post Graduate Programmes, promoting collaborative research among universities, strengthening of the research infrastructure, creation of research positions and enhancing fellowships, are integral to the reforms envisaged in the Eleventh Five Year Plan.

श्री मंगनी लाल मंडल : माननीय सभापति महोदय, मेरा जो प्रश्न है , सरकार ने उसका नकारात्मक उत्तर दिया है । "क" से लेकर "घ" तक सरकार ने सबसे पहले कहा है कि जो आपने प्रश्न पूछा है, वह नहीं है । हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिस्पर्द्धा है, वैश्विक शिक्षा व्यव्था है, उसमें भारत कम्पीट नहीं पाता है, प्रतिस्पर्द्धा में मुकाबला नहीं कर पाता है । जो शोध् पत्र हैं, जो शोध् पेपर तैयार होते हैं, इनकी संख्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिन-प्रतिदिन घटती चली जा रही हैं । न सिर्फ विकसति देशो के मुकाबले में बल्कि विकासशील देशों में जैसे चीन है उसके मुकाबले में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे शोध पत्रों की संख्या दिन-प्रतिदिन घट रही है । सरकार ने ज्ञान आयोग का गठन किया था ।

tOriginal notice of the question was received in Hindi.

था । ज्ञान आयोग ने हमारी शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण करके बताया कि यह वैश्विक स्तर पर नहीं आती है ....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए ।

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, मैं उसी आलोक में पश्न पूछना चाहता हूं कि वैश्विक स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसके कितने मानक और कारक है, जिनको भारत फुलफिल करता है, उनको प्रतिपूर्ण करता है? नम्बर दो, विकसित और विकासशील देशों के मुकाबले में, खास कर चीन के मुकाबले में प्रति वर्ष कितने शोध् पत्र भौतिक शास्त्र में, रसायन शास्त्र में, गणित और दूसरे विज्ञान में ....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए ।

श्री मंगनी लाल मंडल : हम डालते हैं, इसमें हम कितना मुकाबला करते हैं, गुणवत्ता की दृष्टि से कितने चयनित होते है, यह पूरक प्रश्न मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं?

SHRIMATI D. PURANDESWARI: Mr. Chairman, Sir, through you, I would like to apprise the House that there is no one particular global system of education due to wide variations in the education system in different countries. Education system in different countries is geared up for the social and economic needs of that particular country. So, there is not one standardised global system of education that exists. Even when it comes to the evaluation of universities and institutes globally, there is no authentic official international agency which actually can rank universities internationally because the parameters are different from country to country. For example, one parameter says that the number of noble laureates that come out of the university is required to be taken into consideration. But, unfortunately, that cannot be applicable to our country. The number of PhDs in basic sciences and technologies has been a matter of concern to us. One of the reasons is that research has been dominated by the Council for Scientific and Industrial Research. Somehow, the Council needs to come closer to the universities and there needs to be a stronger link between the CSIR and the universities. We are working on that. There is a Committee set up under the Chairmanship of the Secretary, Higher Education, who is actually looking into the aspects of how research in CSIR and universities can be strengthened and how linkages can be strengthened. Coming to the Doctorate degrees that have been awarded in 2003-04 and 2004-05,1 have the list with me. In 2004-05, in Arts, it is 7,532; in Science, it is 5,549; in Commerce and Management, it is 1010; in Education, it is 491; in Engineering and Technology, it is 968; in Medicine, it is 456; in Agriculture, it is 888; in Veterinary Science, it is 132; in Law, it is 179, and in Others, it is 693.

So, in all, during the year 2004-05, we had 17,898 Doctorate degrees awarded, and in 2005-06, it has increased to 18,730. So, I dont think it is correct to say that the Doctorate awardees are less in number. But we are seized of the fact that we need to strengthen the research in the country.

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, मंत्री महोदय ने अच्छा जवाब दिया है । वह अच्छा जवाब देती है, मैं इनकी तारीफ करता हूं, प्रशंसा करता हूं ।

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए ।

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, मैं वही पूछा रहा हूं । माननीय मंत्री महोदय अच्छा जवाब देती है, तो उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, लेकिन उनकी ओर से एक बिन्दु का जवाब नहीं आया । मैंने विकसित देशों और विकासशील देशों की चर्चा की है, तो जो शोध पत्र है और गणित में और भौतिकी में दिनानुदिन छात्रों की जो अभिरूचि कम होत जा रही है, क्या सरकार के पास इस बात के आंकडे हैं ? इसके अतिरिक्त मैं दो बातें जानना चाहता हूं कि सराकर ने ज्ञान आयोग

की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है, तो ज्ञान आयोग की अनुशंसाओं के साथ-साथ सरकार के पास जो विशषणात्म्क टिप्पणियां हैं,जिनकी ओर इंगित किया गया है, वे क्या हैं और सरकार ने उसकी अनुशंसाओं को कितना लागू करने का निर्णय लिया है? तीसरी बात यह है कि माननीय मंत्री महोदया ने अपने उत्तर में 11वीं पंचवर्षीय योजना का उल्लेख् किया है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना को, जिसे सरकार वैश्विक दृष्टिकोण का समझती है, उसको पूरा करने के लिए, उसके कार्यान्वयन के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिया है? यह मेरा द्वितीय पूरक प्रश्न है ।

SHRIMATI D. PURANDESWARI: Sir, the recommendations of the National Knowledge Commission have been kept in mind when the Eleventh Five Year Plan was actually being finalised, and most of the recommendations have been incorporated in that. And, some of them are still under consideration. But, particularly, with reference to the setting up of Institutes in Educationally backward blocks, -- 370 of them have now been identified— setting up Central Universities in such States which does not have them, setting up of world-class universities, these are all recommendations that have been made by the National Knowledge Commission, and they were kept in mind while the Eleventh Five Year Plan was being formed.

DR. KARAN SINGH: Sir, before I put my supplementary, I would just make a submission that this is such an important matter that, if possible, in the second half of this Session, you could give us one day when the House could really discuss education in its depth. I am sure the hon. Members from all over the House, will be keen for it.

My specific supplementary is this. Despite all weaknesses of our system, of our products, our IIMs, our IITs, and our medical colleges, have done very well around the world. Nonetheless, the Knowledge Commission has made certain important recommendations. Have those recommendations been brought before the House? Will they be discussed in the House? Or, will the Government come out with a policy statement as to what exactly they are going to do with those very significant recommendations made by the Knowledge Commission?

SHRIMATI D. PURANDESWARI: Sir, as rightly pointed out by the hon. Member, our students have been placed very well globally. For example, 12 per cent of the scientists in the United States are Indians. We have 38 per cent of the Doctors in the U.S. who are again Indians. Thirty-six per cent of the NASA scientists are again Indians. So, the students are doing very well, and they are reaching places which again reflects on the quality of education that is being provided to out children in our country. But, with reference to recommendations made by the Knowledge Commission, they are with the Planning Commission. Since they are with the Planning Commission, I don't think we can bring the same to the House immediately.

DR. K. MALAISAMY: Sir, it is a very good question which has been put to the hon. Member, and by virtue of the word power and vocabulary skill in the reply of the hon. Minister, it looks as if everything is in order. I am sorry to make such a remark...

MR. CHAIRMAN: Please put your supplementary.

DR. K. MALAISAMY: I want a specific, free and frank, opinion from the hon. Minister.

MR. CHAIRMAN: What is the question?

DR. K. MALAISAMY: Sir, my information is that, of late, many of the doctorates, which are coveted degrees, are easily obtainable and purchasable by certain methods. I would like to know whether this is true or not. If it is true, what effective measures will be taken to prevent it?

SHRIMATI D. PURANDESWARI: Sir, I would request the hon. Member to bring to our notice, if any such instances have come to his notice, so that we could take action. But to put down our education system and say that it is not merit-driven, 1 think, is very, very unfortunate because merit has always been the criterion and it has been the constant endeavour of the Government to ensure that merit and quality is improved in our education system. Through you, Sir, I would request the hon. Member to kindly take note of this.

डा0 मुरली मनोहर जोशी : सभापति जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । पहले तो मैं डा0 कर्ण सिंह जी से सहमत हूं कि इस पर पूरी बहस होनी चाहिए । दूसरी बात यह है कि यह कहना कि विदेशों में हमारे जो छात्र गए हैं, वे हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारी रिसर्च फैसिलिटीज की वजह से वहां पर अच्छा कार्य कर रहे हैं, यह बात बिल्कुल गलत है । सच यह है कि वे छात्र अच्छे हैं, इसलिए वे अच्छा कर रहे हैं । यह गलतफहमी किसी को नहीं रहनी चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालयों में ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से वे वहां पर हैं ।

मैं जानता हूं और सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इन्हें मालूम है कि हमारे छात्रों के रिसर्च साइटेशन्स, यानी जो पेपर्स वे पब्लिश करते हैं, वे निरंतर घट रहे हैं । विश्वविद्यालयों से निकलने वाली मौलिक रिसर्च निरंतर घट रही है । अभी जो आदरणीय सदस्य ने बताया कि बिना कुछ किए हुए, नॉन मैरिटोरियस ढंग से रिसर्च हो रही है और डिग्री मिल रही है , यह सच है । स्वयं मैंने और मध्य प्रदेश के बहुत से लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री जी को ऐसा केस बताया था, जिसके बारे में यह रिपोर्ट है कि वहां plagiarism है और फेक डिग्री है, लेकिन उसके बाद भी उसको नियुक्ति पर बहाल रखा गया । दूसरी ओर एक वाइस चांसलर इसलिए हटाए गए क्योंकि उन्होंने plagiarism किया था । मेरे कहने का तात्पर्य यह कि हमें यहां इस सदन में यह बात साफ स्वीकार करनी चाहिए कि हमारे यहां मौलिक अनुसंधान का स्तर घटा है और उसको बढाने के लिऐ हमें क्या उपाय करने चाहिए, उस पर सदन में बहस होनी चाहिए एवं विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए । यह बहुत चिंता का विषय है , क्योंकि अगर यह ऐसे ही होता रहा ...(**व्यवधान**)...

Mr. CHAIRMAN : what is the question, Dr. saheb?

डा0 मुरली मनोहर जोशी : मेरा सवाल यह है कि क्या मंत्री जी, भारत सरकार इन सारे केसिज की , इन सारे मामलों की कोई जांच करवाएगी कि विश्वविद्यालयों से जो रिसर्च निकल रही है, उस रिसर्च का अंतराष्ट्रीय मूल्य क्या है?

How are they rated in international market?

दूसरी बात यह है कि जो रिसर्च के पोपर्स हमारे यहां से छप रहे हैं, विशेषकर विज्ञान के विषयों में उनका साइटेशन इडेक्स क्या है? उनको क्या कोई पढता भी है या नहीं पढता है ? मंत्री महोदया सदन को इसके बारे में बताएं ।

SHRIMATI D. PURANDESWARI: Sir, I am sure, the hon. Member, my senior colleague, who was previously the Minister of HRD, would agree with me that enhancement of quality and merit in our education system has always been the endeavour and the commitment of the Government. He had been the Minister of HRD and, I am sure, he is seized of this. And, the very fact that our children are able to get into very prestigious institutions stands testimony to the fact that our education system is definitely globally reputed and it has"been accepted. '

Sir, one of the criteria is that they look at the number of students who are actually rejected. *(Interruptions)* Sir, let us look at the various all-India entrance examinations that have been taken. For example, to get into IITs every year, around two lakh to two lakh sixty thousand or * two lakh seventy thousand students apply. But the number of students who, for example, got the admission in 2007 was a little over two per cent of the total that applied for admission. This shows everywhere, right across our educational system, merit has been the criterion for entry at various levels of our education.

Again, coming to the doctorate degrees that have been awarded, I have just mentioned that in 2004-05, the number of doctorate degrees awarded were about 17,898; in 2005-06, about 18,730 degrees were awarded. Sir, definitely, there is an increase in research that is

happening. But, yet, again, I emphasise, Sir, we are seized of the fact that we need to do a little more, and we are doing our best in this. The result has been the setting up of the Committee under the chairmanship of the Secretary, Higher Education. The purpose of this Committee is to bring the research that is happening in the CSIR closer to the universities. It is unfortunate that the research is not happening in our universities, that we have seen this link weakening. Sir, we are trying to look at various aspects and trying to ensure and see how we could actually bring research happening in the CSIR into our universities, which, we think, will help us in the future.

MR. CHAIRMAN: Question No. 143.....*(Interruptions)*...

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, we have asked as many times, but we are not given the chance .... *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Three supplementaries, please .....*(Interruptions)*...

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, please give us a chance to put a supplementary.

SHRI B.J. PANDA: Sir, Q. No. 143 ..... *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: There shall be a discussion on this subject. We have already agreed .... *(Interruptions)*...

SHRI V. HANUMANTHA RAO: Sir, I wanted to know for what purpose it is being given. .... *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt her. Please go ahead .....*(Interruptions)*...

डा0 मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय ...(**व्यवधान**)... **क्या इस पर डिस्कशन के लिए कोई** तारीख तय हुई है ? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: We will work that out in the Business Advisory Committee

Scheme for adolescent girls

* 143. SHRI B.J. PANDA: Will the Minister of WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is proposed to launch a new Central scheme for adolescent girls, to provide a package of compulsory services to them;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether this scheme is propose to be implemented through Anganwadi centres; and

(d) if so, the details thereof, *inter alia* indicating its action plan to implement this project in Orissa?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) It is proposed to merge the two existing schemes, the Kishori Shakti Yojana and the Nutrition Programme for Adolescent girls presently under implementation by the Ministry, and formulate a comprehensive scheme for adolescent girls in the country. The details of the Scheme are being worked out.